PRGI. No.: MHMUL/25/A2419

प्यूपिल्स टाइम्स
PUPILS TIMES

Volume : 1 ‣ Issue : 20 ‣ Mumbai ‣ Friday, 19 June to 25 June 2026 ‣ Weekly ‣ Pages : 8 ‣ Price : 3 Rs.

संक्षिप्त खबरें

आईपीएस सुंदरराज बने एनआईए में आईजी

नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित बस्तर क्षेत्र में लंबे समय तक सेवाएं देने वाले वरिष्ठ आइपीएस अधिकारी सुंदरराज पी को राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) में आइजी के पद पर नियुक्त किया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस संबंध में छत्तीसगढ़ सरकार को पत्र जारी कर उनकी प्रतिनियुक्ति को मंजूरी दे दी है। गृह मंत्रालय द्वारा भेजे गए पत्र में कहा गया है कि वर्ष 2003 बैच के आइपीएस अधिकारी सुंदरराज पी को सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के बाद केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर एनआइए भेजा जा रहा है। राज्य सरकार से उन्हें तत्काल प्रभाव से कार्यमुक्त करने का अनुरोध किया गया है, ताकि वे केंद्र में अपनी नई जिम्मेदारी संभाल सकें।

पीएम नरेंद्र मोदी से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कर दिया बड़ा वादा

'भारत पर हमला हुआ तो हम मदद करेंगे'

पेरिस: फ्रांस में आयोजित जी-7 शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के बीच अहम द्विपक्षीय बैठक हुई। इस मुलाकात में दोनों नेताओं ने कई वैश्विक और द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा की। बैठक के दौरान ट्रंप ने भारत के समर्थन में बड़ा बयान देते हुए कहा कि यदि नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री रहते भारत पर कोई हमला होता है तो अमेरिका मदद के लिए खड़ा रहेगा। ट्रंप का यह बयान ऐसे समय आया है जब दुनिया के कई हिस्सों में भू-राजनीतिक तनाव बना हुआ है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री मोदी की कार्यशैली और व्यक्तित्व की भी सराहना की। उन्होंने कहा कि मैं प्रधानमंत्री मोदी जितना शांत, संयमित और प्रभावशाली नहीं हूं। आप उन्हें देखिए। (शेष पेज-5 पर देखें)

भारत को लेकर ट्रंप ने क्या बड़ा संदेश दिया?

■ बैठक के दौरान ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि मोदी एक बेहद मजबूत नेता हैं और बातचीत के दौरान बहुत सख्त रुख अपनाते हैं। ट्रंप ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी शांत दिखाई देते हैं, लेकिन बातचीत और समझौते के मामले में बेहद सख्त हैं। उन्होंने यह भी कहा कि अगर भारत को किसी तरह का सुरक्षा संकट झेलना पड़ता है तो अमेरिका उसके साथ खड़ा रहेगा। ट्रंप के इस बयान को भारत-अमेरिका रणनीतिक संबंधों के संदर्भ में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

तमिलनाडु के किसानों को सीएम विजय का तोहफा

75 हजार रुपये तक का कर्जा माफ

चेन्नई: तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने किसानों के लिए एक बड़ी राहत की घोषणा की। उन्होंने सहकारी बैंकों से लिए गए 75,000 रुपये तक के फसली कर्ज को पूरी तरह माफ करने का ऐलान किया है। यह छूट उन किसानों को मिलेगी जिन्होंने एक मई 2025 से 28 फरवरी 2026 के बीच कर्ज लिया था। सरकार के इस फैसले से राज्य के 14.43 लाख किसानों को सीधा फायदा होगा। इस कर्ज माफी से सरकारी खजाने पर 5,932 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। मुख्यमंत्री ने सचिवालय में मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक के बाद यह फैसला लिया। सरकार का कहना है कि इससे किसानों को बड़ी राहत मिलेगी। बैठक के बाद जारी जानकारी के अनुसार, जिन किसानों ने 75,000 रुपये

से ज्यादा का कर्ज लिया है, उन्हें भी राहत दी गई है। ऐसे किसानों का 35,000 रुपये का कर्ज माफ किया जाएगा। पिछले महीने सरकार ने छोटे और सीमांत किसानों के लिए 50,000 रुपये तक की कर्ज माफी का एलान किया था। किसानों की मांग के बाद अब सरकार ने इस योजना के दायरे को बढ़ा दिया है। भारतीय रिजर्व बैंक के नियमों के अनुसार, सरकार को कर्ज माफी की पूरी राशि 45 से 60 दिनों के भीतर जारी करनी होगी। राज्य की आर्थिक स्थिति चुनौतीपूर्ण होने के बावजूद मुख्यमंत्री ने लगभग 6,000 करोड़ रुपये की इस राहत पैकेज को मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री विजय ने

कहा कि इस फैसले से किसानों को अगली खेती के सीजन के लिए नया कर्ज लेने में बहुत मदद मिलेगी।

रक्षा आधुनिकीकरण का दशक

स्वदेशी क्षमता से रणनीतिक महाशक्ति बनने की ओर भारत

नई दिल्ली: पिछले एक दशक में भारत ने रक्षा क्षेत्र में उल्लेखनीय परिवर्तन दर्ज किया है। यह बदलाव केवल सैन्य आधुनिकीकरण तक सीमित नहीं रहा, बल्कि स्वदेशी अनुसंधान, तकनीकी नवाचार, रक्षा उत्पादन और वैश्विक रणनीतिक साझेदारियों के विस्तार के माध्यम से राष्ट्रीय सुरक्षा के व्यापक सुदृढ़ीकरण के रूप में सामने आया है। भारत ने अपनी रक्षा क्षमताओं को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाते हुए एक विश्वसनीय सुरक्षा भागीदार और उभरती वैश्विक शक्ति के रूप में अपनी पहचान मजबूत की है। पिछले 12 वर्षों में भारत की रक्षा यात्रा केवल सैन्य आधुनिकीकरण की कहानी नहीं है, बल्कि यह एक ऐसे राष्ट्र के उदय

का प्रतीक है जो अपनी स्वदेशी क्षमताओं के बल पर अपने रणनीतिक भविष्य को सुरक्षित करने के लिए प्रतिबद्ध है। युद्धपोतों, लड़ाकू विमानों, ड्रोन, मिसाइल प्रणालियों और उन्नत इलेक्ट्रॉनिक्स से लेकर रक्षा उत्पादन में निजी क्षेत्र, स्टार्टअप्स तथा एमएसएमई की बढ़ती भागीदारी तक, देश ने एक व्यापक और नवाचार-आधारित रक्षा पारिस्थितिकी तंत्र विकसित किया है।

जुलाई से लागू होगा भारत-ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौता

व्यापार और निवेश को मिलेगा बढ़ावा

नई दिल्ली: भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच हुआ ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौता (एफटीए) 15 जुलाई 2026 से लागू हो जाएगा। दोनों देशों ने बुधवार को इसकी आधिकारिक घोषणा की। इस समझौते के लागू होने के बाद

भारत और ब्रिटेन के कारोबारियों को बड़े स्तर पर शुल्क (टैरिफ) में राहत मिलेगी और दोनों देशों के बीच व्यापार को नई गति मिलेगी। यह समझौता हस्ताक्षर होने के बाद सबसे तेजी से लागू होने वाले व्यापार समझौतों में से एक माना जा रहा है। अब कारोबारियों के पास इसकी तैयारियां पूरी करने के लिए 28 दिन का समय है। ब्रिटेन सरकार के अनुसार, इस समझौते से लंबे समय में ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था (जीडीपी) में लगभग 4.8 अरब पाउंड की बढ़ोतरी होगी। (शेष पेज-5 पर देखें)

जीडीपी का छह प्रतिशत शिक्षा पर खर्च हो : संसदीय समिति

नई दिल्ली: संसद की एक समिति ने उच्च शिक्षा के लिए मौजूदा बजटीय आवंटन को अपर्याप्त करार दिया। समिति ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 के अनुरूप शिक्षा पर व्यय बढ़ाकर सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का छह प्रतिशत करने की अनुशंसा की। राज्यसभा सदस्य दिग्विजय सिंह की अध्यक्षता वाली शिक्षा, महिला, बाल, युवा एवं खेल संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने मंगलवार को उच्च शिक्षा विभाग की वर्ष 2025-26 की अनुदान मांगों पर आधारित अपनी रिपोर्ट राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन को सौंपी। समिति ने कहा कि वर्ष 2024-25 की तुलना में वर्ष 2025-26 के लिए उच्च शिक्षा विभाग के बजट आवंटन में हुई वृद्धि पिछले साल के मुकाबले कम

रही। समिति का मानना है कि मुद्रास्फीति को देखते हुए बजटीय आवंटन में कम से कम आठ से 10 प्रतिशत की वृद्धि होनी चाहिए। समिति ने यह भी कहा कि वर्ष 2018 से 2023 के दौरान पुरुषों और महिलाओं का सकल नामांकन अनुपात रोजगार तथा मानव संसाधन के समुचित विकास के उद्देश्य से उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज नहीं कर सका है। समिति ने सिफारिश की है कि वर्ष 2035 के लिए एनईपी-2020 में निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप शिक्षा पर व्यय का प्रतिशत और बढ़ाया जाए। (शेष पेज-5 पर देखें)

GDP का 6% निवेश क्यों है जरूरी?

■ राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP-2020) में केंद्र और राज्य सरकारों को शिक्षा पर सार्वजनिक निवेश बढ़ाकर GDP का 6 प्रतिशत करने का लक्ष्य दिया गया था। हालांकि, रिपोर्ट के अनुसार, 2021-22 में भारत का कुल शिक्षा व्यय GDP का मात्र 4.12 प्रतिशत रहा। समिति का मानना है कि भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए निवेश का यह आंकड़ा बढ़ाना बेहद जरूरी है।

संपादकीय

जी-7 की बैठक

फ्रांस में जी-7 की बैठक के चलते विश्व का ध्यान उन्नत अर्थव्यवस्थाओं और लोकतंत्र वाले देशों के इस संगठन की ओर जाना स्वाभाविक है। वैसे तो इस संगठन के सदस्य देशों में अमेरिका के अतिरिक्त ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, कनाडा और जापान भी शामिल हैं, लेकिन कुल मिलाकर इस पर अमेरिका का ही दबदबा रहता है। प्रति वर्ष जब भी जी-7 देशों की बैठक होती है तो यह संगठन चर्चा में तो आता है, लेकिन अभी तक का अनुभव यही बताता है कि वह कोई विशेष प्रभाव नहीं छोड़ पाता। इस बार भी ऐसा ही हो तो हैरत नहीं, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप सदस्य देशों को सहयोगी कम, अपना अनुयायी अधिक समझते हैं। राष्ट्रपति के रूप में अपने इस दूसरे कार्यकाल में उन्होंने करीब-करीब सभी सदस्य देशों के साथ टैरिफ और अन्य मामलों में मनमाना व्यवहार किया है। कुछ सदस्य देशों के साथ तो उन्होंने बहुत ही बुरा बर्ताव किया है। उनके अपनी ही चलाने वाले रवैये के कारण अमेरिका के अन्य देशों के साथ मतभेद बढ़े हैं। इसे देखते हुए इसके आसार कम ही हैं कि यह संगठन टैरिफ, जलवायु परिवर्तन, एआइ के उचित उपयोग आदि के मामले में किसी सहमति पर पहुंच कर ऐसे कोई निर्णय ले पाएगा, जो विश्व की समस्याओं के समाधान में सहायक बनेंगे। यह एक तथ्य है कि आपसी मतभेदों के कारण ही जी-7 संगठन न तो रूस-यूक्रेन युद्ध को थाम पाया और न ही पश्चिम एशिया संकट समेत अन्य वैश्विक समस्याओं को समय रहते सुलझा सका। इस बार बैठक का एक प्रमुख एजेंडा व्यापारिक असंतुलन दूर करना भी है, लेकिन इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि इस असंतुलन का एक बड़ा कारण तो खुद अमेरिका है। ट्रंप के नेतृत्व में अमेरिका ने सदस्य देशों के साथ ही अन्य कई देशों पर जैसी धौंस जमाने की कोशिश की है, उसकी मिसाल मिलना कठिन है। चूंकि पिछले वर्षों की तरह इस बार भी भारतीय प्रधानमंत्री को मेहमान के रूप में इस संगठन में आमंत्रित किया गया है, इसलिए भारत के साथ विकासशील एवं निर्धन देशों का ध्यान भी इस बैठक की ओर जाएगा, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने इन देशों की आकांक्षाओं को रेखांकित करने की बात कही है। वे पहले भी ऐसा करते रहे हैं। जी-7 बैठक के दौरान भारतीय प्रधानमंत्री की अमेरिकी राष्ट्रपति से अलग से मुलाकात होने के चलते यह भी विशेष रूप से देखा जा रहा है कि दोनों देशों के संबंधों में व्यापक सुधार का रास्ता साफ नजर नहीं आ रहा है? यदि अमेरिका इस संगठन को प्रभावी बनाना चाहता है तो उसे सदस्य देशों के साथ समानता का व्यवहार करना होगा। निःसंदेह ऐसी ही अपेक्षा भारत और अन्य मेहमान देशों की भी रहेगी। अमेरिकी राष्ट्रपति को यह आभास होना चाहिए कि अब अमेरिका पहले जितना सक्षम नहीं रहा।

भारतीय रेलवे ने विद्युतीकरण के माध्यम से डीजल की भारी बचत की है

पिछले दिनों पश्चिम एशिया संकट को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देशवासियों से पेट्रोल-डीजल का सीमित और समझदारी से इस्तेमाल करने की अपील की। उन्होंने विशेष रूप से कहा कि सार्वजनिक परिवहन के उपयोग को बढ़ावा दें और जहां निजी वाहन की जरूरत हो वहां कारपूलिंग अपनाई जाए। उन्होंने कहा कि हमें विदेशी मुद्रा बचानी होगी। प्रधानमंत्री की अपील का जनता पर कितना असर पड़ा यह तो आने वाला समय ही बताएगा, लेकिन भारतीय रेल द्वारा विद्युतीकरण मुहिम के जरिये डीजल की बचत की जा रही है। वित्त वर्ष 2024-25 में भारतीय रेल ने विद्युतीकरण के जरिये 185 करोड़ किलो लीटर डीजल बचाया। यह मात्रा देश की कुल चार दिन की डीजल की मांग के बराबर है। सबसे बड़ी बात यह है कि विद्युत कर्षण (रेल के पहियों को खींचने में लगने वाली ऊर्जा) पर्यावरण के अनुकूल होने के साथ-साथ डीजल ट्रैक्शन की तुलना में 70 प्रतिशत किफायती भी है। उल्लेखनीय है कि 2014 से पहले देश में मात्र 21,801 किलोमीटर रेल लाइनों का विद्युतीकरण हुआ था। इसी को देखते हुए प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी ने रेल विद्युतीकरण को प्राथमिकता दी। तत्कालीन रेल मंत्री के निर्देशन में रेल विद्युतीकरण मिशन शुरू किया गया। इस मिशन का लक्ष्य रेलवे के पूरे नेटवर्क का 100 प्रतिशत विद्युतीकरण करना है। रेलवे ने यह मिशन डीजल इंजनों से होने वाले प्रदूषण को कम करने और ट्रेनों की सामान्य गति को बढ़ाने के लिए तैयार की है। डीजल इंजनों की कार्यक्षमता काफी कम होती है और इन्हें चलाने में बहुत लागत आती है। मार्च 2026 तक रेलवे के कुल 70,175 किलोमीटर ब्राडगेज नेटवर्क में 69,906 किलोमीटर नेटवर्क का विद्युतीकरण किया जा चुका है। अर्थात कुल ब्राडगेज नेटवर्क

का 99.6 प्रतिशत विद्युतीकृत किया जा चुका है। अब मात्र 269 किलोमीटर रेलवे नेटवर्क ऐसा है, जिसका विद्युतीकरण किया जाना बाकी है। जिन राज्यों में रेल विद्युतीकरण अभी लंबित है, उनमें गोवा, तमिलनाडु, कर्नाटक, असम और राजस्थान शामिल हैं। गोवा में 91 प्रतिशत, तमिलनाडु में 97 प्रतिशत, कर्नाटक में 97 प्रतिशत, असम में 98 प्रतिशत, राजस्थान में 99 प्रतिशत काम पूरा हो चुका है। वर्ष 2014 से पहले देश में प्रतिदिन औसत 1.42 किलोमीटर रेल लाइनों का विद्युतीकरण हुआ। वहीं रेल विद्युतीकरण मिशन शुरू होने के बाद 2019-2025 में प्रतिदिन औसतन 15 किलोमीटर रेललाइनों का विद्युतीकरण किया गया। 2023-24 में रेल विद्युतीकरण का रिकार्ड बना जब प्रतिदिन औसतन 19.7 किलोमीटर रेल लाइनों का विद्युतीकरण हुआ। यह परिवर्तन भारतीय रेल को अधिक तेज, स्वच्छ और आत्मनिर्भर बनाते हुए नए भारत की विकास रीढ़ को और मजबूत कर रहा है। स्पष्ट है कि 1925 में बांबे वीटी (वर्तमान छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस) और कुर्ला के बीच हार्बर लाइन पर चली पहली बिजली चालित रेलगाड़ी के 100 वर्ष बाद भारतीय रेल ने शत प्रतिशत विद्युतीकरण का लक्ष्य हासिल कर लिया है। रेल विद्युतीकरण के मामले में भारत दुनिया की कई अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं को पीछे छोड़ चुका है। जहां भारत में 96.6 प्रतिशत रेल लाइनों का विद्युतीकरण हो चुका है वहीं ब्रिटेन में 39 प्रतिशत, रूस में 52 प्रतिशत और चीन में 82 प्रतिशत रेलमार्गों का ही विद्युतीकरण हो पाया है। रेल विद्युतीकरण की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि रेलवे स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों के इस्तेमाल को बढ़ावा दे रहा है। नवंबर 2025 तक रेलवे अपने कुल परिचालन में 898 मेगावाट सौर ऊर्जा का इस्तेमाल कर रहा था। 2014 में मात्र 3.68 मेगावाट सौर ऊर्जा का इस्तेमाल रेलवे कर रहा था। 898 मेगावाट में से 629 मेगावाट का उपयोग रेलगाड़ियों को चलाने के लिए किया जा रहा है, जबकि 269 मेगावाट अन्य जरूरतों को पूरा करने में। इनमें स्टेशन की लाइटिंग, वर्कशाप, सर्विस बिल्डिंग और रेलवे क्वार्टर शामिल हैं। वर्तमान में 2,626 रेलवे स्टेशन सौर ऊर्जा का उपयोग कर रहे हैं। इस तरह के उपाय 2030 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन के लक्ष्य को हासिल करने के लिए भारतीय रेल की प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हैं। भारत ने हाइड्रोजन ऊर्जा मिशन के तहत 2030 तक प्रतिवर्ष 50 लाख टन हरित हाइड्रोजन उत्पादन तथा 2070 तक नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा है। रेलवे ने हरित ऊर्जा स्रोतों को विविधीकरण करते हुए हरियाणा कजींद-सोनीपत रूट पर देश की पहली हाइड्रोजन ईंधन से चलने वाली 10 कोच वाली ट्रेन को मंजूरी दे दी है। इससे प्रदूषण काफी कम होगा। रेलवे अपने ऊर्जा स्रोतों को विविधीकृत कर रहा है। वर्तमान में रेलवे ने अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए 4,260 मेगावाट सौर और 3,427 मेगावाट पवन ऊर्जा के लिए समझौता किया है। इसके अलावा भी रेलवे ने 1,500 मेगावाट रिन्यूएबल एनर्जी के लिए अनुबंध किया है। रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर पावर लिमिटेड अपने सोलर पार्क से भारतीय रेलवे को सौर ऊर्जा की आपूर्ति कर रही है। इसके साथ-साथ 2025-26 में रेलवे ने 81.59 लाख पौधे लगाए, 185 जल पुनर्चक्रण संयंत्र एवं 8,313 वर्षा जल संचयन संरचनाएं भी स्थापित किए। इस प्रकार भारतीय रेल पर्यावरण संरक्षण में मौन क्रांति ला रहा है।

अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते से दुनिया ने राहत की सांस ली है

पर यह अभी भी नाजुक और अनिश्चितताओं से भरा है

अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते पर सहमति बनने की घोषणा के बाद पूरी दुनिया ने राहत की सांस ली है। वित्तीय बाजारों में उत्साह दिखा तो कच्चे तेल की कीमतें नरम पड़ीं। हालांकि उम्मीद की इस किरण के पीछे कुछ आशंका भी है। ऐसा इसलिए, क्योंकि यह कोई अंतिम शांति संधि नहीं है, बल्कि भविष्य की वार्ताओं के लिए एक रूपरेखा मात्र है। यह समझौता तत्काल संघर्ष को रोकने और अमेरिका तथा ईरान के संबंधों को नई दिशा देने का अवसर अवश्य प्रदान करता है, किंतु यह अभी भी नाजुक, विवादास्पद और अनिश्चितताओं से घिरा हुआ है। वैसे भी कागज पर हुई शांति हमेशा धरातल पर साकार रूप नहीं ले पाती। पिछले कुछ महीनों में हिंसक संघर्ष ने पूरे क्षेत्र को एक व्यापक युद्ध की आशंका से भर दिया था। ईरान, इजरायल और इस क्षेत्र के अनेक गैर-राज्यीय समूह आमने-सामने खड़े दिखाई दे रहे थे। इस संघर्ष का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र होर्मुज जलमार्ग बन गया था, जहां से विश्व के लगभग पांचवें हिस्से का तेल गुजरता है। इस जलमार्ग के अवरुद्ध होने से वैश्विक ऊर्जा बाजारों में भारी उथल-पुथल मच गई थी और दुनिया भर में महंगाई बढ़ने की आशंका पैदा हो गई थी। इस जलमार्ग का फिर से खुलना और अमेरिकी नौसैनिक नाकेबंदी के हटने से न केवल सैन्य टकराव का खतरा घटा है, बल्कि वैश्विक व्यापार और ऊर्जा आपूर्ति के सामान्य होने की उम्मीद भी जगी है। हालांकि प्रमुख शिपिंग कंपनियों ने संकेत दे दिया है कि होर्मुज से सामान्य आवाजाही बहाल होने में महीनों लग सकते हैं। समुद्री बीमा की लागत अब भी ऊंची है, बंदरगाहों और अन्य बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचा है और सबसे महत्वपूर्ण यह है कि इस समझौते की स्थिरता को लेकर अभी भी भरोसा नहीं बन पाया है। बाजार सकारात्मक खबरों पर तुरंत प्रतिक्रिया दे सकते हैं, लेकिन व्यापार जगत केवल घोषणाओं पर नहीं, बल्कि स्थायी स्थिरता पर भरोसा करता है। इस समझौते की सबसे बड़ी चुनौती ईरान के परमाणु कार्यक्रम का मुद्दा है, जिसने दोनों देशों के संबंधों को दशकों से उलझाए रखा है। अमेरिकी प्रशासन का दावा है कि ईरान ने कभी परमाणु हथियार न बनाने पर सहमति व्यक्त की है। जबकि ईरान का कहना है कि वर्तमान समझौता केवल प्रारंभिक ढांचा है और परमाणु मुद्दे पर वास्तविक बात बाद में होगी, जब दूसरे पक्ष अपने शुरुआती दायित्वों को पूरा करेंगे। दोनों पक्षों की यह विरोधाभासी व्याख्या किसी तकनीकी अंतर का प्रश्न नहीं है, बल्कि यही इस समझौते की कमजोरी का मूल कारण

भी है। ईरान पर प्रतिबंधों का मुद्दा भी उतना ही विवादास्पद है। कुछ रिपोर्टों में कहा गया है कि ईरान को उसकी जब्त संपत्तियों तक पहुंच मिल सकती है और तेल निर्यात पर लगे प्रतिबंधों में ढील दी जा सकती है। अमेरिकी प्रशासन इन बातों से इन्कार करते हुए कहता है कि आर्थिक लाभ तभी मिलेंगे, जब ईरान अपने दायित्वों का पालन करेगा। यह अस्पष्टता फिलहाल दोनों सरकारों के लिए राजनीतिक रूप से उपयोगी हो सकती है, क्योंकि वे घरेलू स्तर पर इसे अपनी जीत के रूप में पेश कर सकती हैं, लेकिन भविष्य में यही अस्पष्टता गंभीर विवाद का कारण भी बन सकती है। अमेरिका और ईरान दोनों की घरेलू राजनीति इस समझौते के भविष्य को प्रभावित करेगी। अमेरिका में रिपब्लिकन और डेमोक्रेट दोनों दलों के सांसदों ने समझौते के बारे में अधिक जानकारी मांगी है। कई सांसद इससे असंतुष्ट हैं कि कांग्रेस को भरोसे में नहीं लिया गया। ट्रंप प्रशासन ने फिलहाल भले ही एक कूटनीतिक गुंजाइश बनाई हो, लेकिन इसे स्थायी समझौते में बदलने के लिए उसे गहरे राजनीतिक विभाजन से जूझना पड़ेगा। ट्रंप के लिए यह समझौता राजनीतिक दृष्टि से लाभकारी कहा जा सकता है। मध्यावधि चुनावों से पहले जारी युद्ध, तेल की ऊंची कीमतें और अनिश्चित परिणाम उनकी राजनीतिक संभावनाओं को नुकसान पहुंचा सकते थे। इसके विपरीत यह समझौता उन्हें एक निर्णायक और शांति स्थापित करने वाले नेता के रूप में प्रस्तुत करने का अवसर देता है। उनके समर्थक इसे सैन्य दबाव के परिणाम के रूप में देख सकते हैं, जबकि आलोचक यह सवाल उठाते रहेंगे कि क्या यह युद्ध कभी आवश्यक था भी या नहीं। ईरान का दावा है कि महीनों के संघर्ष के बावजूद उसकी सरकार कायम रही, उसके क्षेत्रीय सहयोगी सुरक्षित रहे और पश्चिम एशिया में उसका प्रभाव कम नहीं हुआ। ईरानी नेतृत्व का मानना है कि अमेरिका और इजरायल अपने व्यापक राजनीतिक उद्देश्यों को हासिल करने में असफल रहे। कोई भी पक्ष कमजोर दिखाई नहीं देना चाहता और यही कारण है कि आगे की वार्ताएं और कठिन हो सकती हैं। इजरायल की स्थिति इस समझौते को और अधिक जटिल बनाती है, क्योंकि उसके प्रधानमंत्री नेतन्याहू इस समझौते को लेकर उत्साहित नहीं दिखते। वे पहले ही संकेत दे चुके हैं कि इजरायली सैनिक दक्षिणी लेबनान में बने रहेंगे और यदि उन्हें किसी खतरे की आशंका होगी तो वे सैन्य कार्रवाई से हिचकेंगे नहीं। अंतरराष्ट्रीय समुदाय यही चाहेगा कि यह समझौता टिकाऊ बने, क्योंकि संघर्ष छिड़ने से व्यापक आर्थिक समीकरण फिर से गड़बड़ाएंगे। यह समझौता कोई गंतव्य न होकर उसकी दिशा में प्रस्थान ही है। यह कठिन प्रश्नों का समाधान नहीं करता, बल्कि उन्हें भविष्य के लिए टाल देता है।

मुंबई में जल संकट गहराया

बीएमसी ने जलापूर्ति में 20 प्रतिशत की कटौती की

मुंबई: मानसून में देरी के चलते मुंबई में पानी की संकट गहरा गया है। आर्थिक राजधानी के जलाशयों के जलस्तर घटकर 10.35 प्रतिशत रह जाने के मद्देनजर बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) ने औद्योगिक, व्यावसायिक और खेल प्रतिष्ठानों को होने वाली जलापूर्ति में 20 प्रतिशत कटौती करने की घोषणा की। बीएमसी ने निर्माण कार्य परियोजनाओं और स्विमिंग पूलों के लिए पानी के कनेक्शन भी तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिए गए हैं। जलापूर्ति में कटौती संबंधी यह निर्णय बुधवार से प्रभावी होगा। बीएमसी ने पहले ही 15 मई 2026 से शहर में 10 प्रतिशत पानी कटौती लागू कर दी थी। अब पेयजल संरक्षण के लिए 17 जून से अतिरिक्त प्रतिबंध लागू किए जा रहे हैं। इसके तहत नए निर्माण कार्यों के लिए पानी के नए कनेक्शन की मंजूरी पर रोक लगा दी गई है, जबकि मौजूदा निर्माण स्थलों और सभी स्विमिंग पूलों की जल आपूर्ति अस्थायी रूप से बंद की जाएगी। औद्योगिक, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों और स्पोर्ट्स क्लबों को मिलने वाले पानी में 20 प्रतिशत की कटौती की गई है। बिसलेरी जैसी कंपनियों के बोतलबंद पानी और एरेटेड ड्रिंक यानी कोकाकोला, पेप्सी, स्प्राइट, फैंटा बनाने वाले प्लांट्स को केवल

कर्मचारियों की पीने की जरूरत के हिसाब से सीमित पानी दिया जाएगा। बीएमसी ने चेतावनी दी है कि पेयजल का दुरुपयोग या बबार्दी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं, नागरिकों से पानी बचाने में सहयोग की अपील भी की है।

रोजना आपूर्ति के लिए भी पूरा पानी नहीं

मुंबई को प्रतिदिन लगभग 4,664 मिलियन लीटर पानी की आवश्यकता होती है, जबकि वर्तमान औसत आपूर्ति 4,100 मिलियन लीटर प्रति दिन है। 16 जून तक, महानगर को पानी की आपूर्ति करने वाली झीलों में संयुक्त जल भंडार कुल क्षमता का केवल 10.35% था, जो पर्याप्त वर्षा होने तक जल आपूर्ति बनाए रखने में एक चुनौती पेश कर रहा है। राज्य के जल संसाधन विभाग के निर्देशों के बाद, बीएमसी पीने के पानी के प्रबंधन के लिए मितव्ययिता उपायों को लागू कर रहा है। सार्वजनिक शौचालयों का संचालन करने वाले संगठनों को टैंकर, कुएं या बोरवेल के पानी के उपयोग को अधिकतम करने का निर्देश दिया गया है। बोरवेल और कुएं के पानी का उपयोग गैर-पीने योग्य उद्देश्यों जैसे वाहन धोने, बागवानी और सड़कों व परिसरों की सफाई के लिए किया जाना चाहिए। प्रमुख प्रतिष्ठानों, जिनमें सेंट्रल रेलवे, वेस्टर्न रेलवे, आरसीएफ, एचपीसीएल, बीपीसीएल, नौसेना, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम (एमआईडीसी) और मुंबई पोर्ट अथॉरिटी को सीवेज उपचार संयंत्रों से उपचारित अपशिष्ट जल का परिचालन और द्वितीयक उद्देश्यों के लिए पुनः उपयोग करने की सलाह दी गई है।

मुंबई में मई में 14 साल में सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन हुए

मुंबई: मुंबई के रेजिडेंशियल रियल एस्टेट मार्केट ने मई 2026 में भी अपनी मजबूत रफ़्तार जारी रखी, जिसमें 12,315 प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन हुए, जो साल-दर-साल 7% की बढ़ोतरी है, जिससे यह पिछले 14 सालों में मई महीने में दर्ज रजिस्ट्रेशन की सबसे ज्यादा संख्या बन गई। महाराष्ट्र सरकार ने महीने के दौरान स्टाम्प ड्यूटी रेवेन्यू में 1,051 करोड़ से ज्यादा भी इकट्ठा किए, जो पूरे शहर में घरों की लगातार डिमांड को दिखाता है। नाइट फ्रैंक इंडिया द्वारा एनालाइज किए गए महाराष्ट्र डिपार्टमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन्स एंड स्टैम्प्स (IGR) के डेटा के अनुसार, नए आंकड़े 2025 में दर्ज पिछले मई के पीक को पार कर गए। हालांकि, लगातार आधार पर, अप्रैल 2026 की तुलना में रजिस्ट्रेशन में 14% की गिरावट आई, जबकि स्टाम्प ड्यूटी कलेक्शन में महीने-दर-महीने 9% की गिरावट आई, जो ग्लोबल आर्थिक अनिश्चितताओं के बीच घर खरीदने वालों के बीच सावधानी का संकेत है।

2025 में दर्ज पिछले मई के पीक को पार

इंडस्ट्री के स्टेकहोल्डर्स का मानना है कि मजबूत सालाना ग्रोथ लगातार एंड-यूजर डिमांड को दिखाती है, जिसे इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड, मेट्रो विस्तार, रीडेवलपमेंट से चलने वाली सप्लाई और मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन में कनेक्टिविटी में सुधार से सपोर्ट मिला है। एक्सपर्ट्स ने यह भी बताया है कि घर खरीदने वाले बड़े इन्वेस्टमेंट के लिए सावधानी भरा रवैया अपनाते हैं।

महाराष्ट्र: राज्य में नकली दवा कंपनियों पर कसेगा शिकंजा

जांच के लिए राज्य सरकार ने बनाई विशेष समिति

मुंबई: राज्य में नकली दवा कंपनियों के बढ़ते खतरे को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने उनके उत्पादों की गहन जांच के लिए एक विशेष समिति का गठन किया है। यह समिति संदिग्ध दवा निर्माण कंपनियों की जांच करेगी और दोषी पाए जाने पर उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की सिफारिश करेगी। इससे प्रदेश में इस तरह की कंपनियों पर शिकंजा कसा जा सकेगा। ज्ञात हो कि विधान परिषद सदस्य अंबादास दानवे द्वारा उठाए गए ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर हुई चर्चा के दौरान खाद्य व औषधि प्रशासन मंत्री ने इस संबंध में आश्वासन दिया था। उसी के अनुरूप राज्य सरकार ने विशेष जांच समिति गठित करने का निर्णय लिया है। इस पृष्ठभूमि में विभाग ने तीन सदस्यीय समिति का गठन किया है। समिति राज्य में कार्यरत संदिग्ध दवा कंपनियों की पहचान कर उनके उत्पादों की जांच करेगी। विशेष रूप से दवाओं में उपयोग किए गए घटकों की वैज्ञानिक तरीके से पड़ताल की जाएगी। जांच पूरी होने के बाद दोषी कंपनियों और संस्थानों के खिलाफ नियमों के अनुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी। नागरिकों के स्वास्थ्य और जीवन से सीधे जुड़े इस अत्यंत संवेदनशील विषय पर राज्य सरकार द्वारा उठाया गया यह कदम महत्वपूर्ण माना जा रहा है। नकली और मिलावटी दवाओं के बढ़ते मामलों को देखते हुए विशेषज्ञ लंबे समय से कड़े नियंत्रण और प्रभावी निगरानी व्यवस्था की मांग कर रहे थे। स्वास्थ्य क्षेत्र के जानकारों का मानना है कि इस पहल से दवा निर्माण, वितरण और बिक्री प्रक्रिया में अधिक पारदर्शिता आएगी।

ठाणे में मानसून पूर्व तैयारियों को लेकर एकनाथ शिंदे सख्त

सड़कों की मरम्मत और क्लस्टर पुनर्विकास के निर्देश

मुंबई: उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने निर्देश दिया है कि मानसून को देखते हुए। ठाणे जिले में सड़क का काम तेजी से पूरा किया जाए। इस बैठक में शिंदे ने निर्देश दिया कि ठाणे जिलाधिकारी की अध्यक्षता में सार्वजनिक निर्माण विभाग, एमएसआरडीसी और एमएमआरडीए को समन्वय बनाकर इन कार्यों में तेजी लानी चाहिए। यह भी कहा कि सड़कों पर बने। गड्ढों को तत्काल भरा जाए, निर्माणाधीन सड़कों को बरसात से पहले अच्छी स्थिति में लाया जाए, जिले में खतरनाक पुलों का स्ट्रक्चरल ऑडिट तुरंत कराया जाए। इसके साथ ही उपमुख्यमंत्री ने सभी मनपाओं को क्लस्टर के पुनर्विकास को प्राथमिकता देने की बात कही है। बैठक में पिछले साल ठाणे जिले के मुरबाड और मुंब्रा में हुए भूस्खलन हादसों के मद्देनजर घाट में चल रहे सुरक्षा कार्यों की समीक्षा की गई। इस दौरान शिंदे ने निर्देश दिए कि इन दोनों जगहों पर 70 फीसदी काम पूरा हो

चुका है और इसे जल्द से जल्द पूरा किया जाए। उन्होंने आशा व्यक्त की कि सभी एजेंसियों को एक-दूसरे के साथ समन्वय में काम करना चाहिए और सतर्क रहना चाहिए ताकि इस वर्ष के मानसून के दौरान कोई जनहानि न हो। इस बैठक में मुख्य रूप से ठाणे जिले में खतरनाक इमारतों के मुद्दे पर चर्चा की गई। उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने सुझाव दिया कि हर साल उन्हीं इमारतों को खतरनाक घोषित करने की बजाय उनकी मरम्मत की जानी चाहिए। उपमुख्यमंत्री शिंदे ने संबंधित नगर पालिकाओं के आयुक्तों को क्लस्टर योजना के माध्यम से भिवंडी कल्याण-डोंबिवली, उल्हासनगर, मुंब्रा क्षेत्र में खतरनाक इमारतों के पुनर्विकास के लिए ठाणे नगर पालिका की तर्ज पर एक क्लस्टर सैल स्थापित करके इन परियोजनाओं को गति देने का निर्देश दिया।

बैठक में शामिल हुए सांसद, डीएम, डीसीएम एवं अन्य

ठाणे जिले में मानसून पूर्व तैयारियों की समीक्षा के लिए मुंबई में एक विशेष बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में सांसद सुरेश म्हात्रे, विधायक किसन कथोरे, विधायक रविंद्र फाटक, ठाणे के कलेक्टर श्रीकृष्ण पांचाल, डिप्टी कलेक्टर संदीप माने, उपमुख्यमंत्री कार्यालय के अतिरिक्त मुख्य सचिव नवीन सोना, ठाणे मनपा आयुक्त सौरभ राव और ठाणे जिले के सभी मनपा के आयुक्त, महापौर, पुलिस आयुक्त और अन्य प्रशासनिक अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उपस्थित थे।

अंबरनाथ में शादी के 48 दिन बाद विशाखा ने की आत्महत्या

डॉक्टर पति घर के अंदर CCTV से रखता था नजर

CCTV कैमरे में कैद थी विशाखा की निजी जिंदगी

गौरव सिंह/अंबरनाथ

ठाणे जिले के अंबरनाथ क्षेत्र से एक बेहद दुखद और दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। यहां शादी के महज 48 दिन बाद एक 26 वर्षीय नवविवाहिता विशाखा तिलकर ने ससुराल वालों के जानलेवा मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न से तंग आकर आत्महत्या कर ली। विशाखा की शादी बीते 30 अप्रैल 2026 को डॉक्टर नितिन तिलकर से हुई थी। मृतका के परिवार का आरोप है कि विवाह से पहले सब कुछ पूरी तरह सामान्य था, लेकिन विदाई के कुछ ही दिनों बाद ससुराल वालों का असली और लालची चेहरा सामने आ गया। विशाखा पर लगातार मायके से मोटी रकम, सोने के गहने और अन्य कीमती सामान लाने का दबाव बनाया जा रहा था। विशाखा के परिजनों ने उसकी वैवाहिक जिंदगी को लेकर जो खुलासे किए हैं, वे रोंगटे खड़े करने वाले हैं। परिजनों के मुताबिक, उसके पति डॉक्टर नितिन तिलकर ने घर के अंदर के कमरों और बाहर के रास्तों पर कई हाई-डेफिनिशन सीसीटीवी कैमरे लगवा रखे थे। इन कैमरों के जरिए विशाखा की हर छोटी-बड़ी गतिविधि, उठने-बैठने और यहां तक कि उसकी सांसों पर भी सख्त नजर रखी जाती थी।

डॉक्टर पति नितिन तिलकर गिरफ्तार

■ इस क्रूर मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न से पूरी तरह टूट चुकी विशाखा ने आखिरकार मौत को गले लगा लिया। इस स्तब्ध कर देने वाली घटना के बाद अंबरनाथ के शिवाजीनगर पुलिस स्टेशन में पीड़ित परिवार की शिकायत पर मुख्य आरोपी पति डॉ. नितिन तिलकर, उसकी मां छाया तिलकर और भाई निनाद तिलकर के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने (IPC 306), घरेलू हिंसा और प्रताड़ना का मामला दर्ज किया गया है। अंबरनाथ पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी पति नितिन तिलकर को सलाखों के पीछे भेज दिया है, जबकि उसकी फरार मां और भाई की तलाश के लिए पुलिस टीमें संभावित ठिकानों पर छापेमारी कर रही हैं।

ठाणे मनपा हजारों विद्यार्थियों को देगी साल तक मुफ्त यूनिफॉर्म

■ योजना को महासभा की मंजूरी का इंतजार

ठाणे: ठाणे महानगरपालिका के स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए एक बड़ी राहतभरी योजना तैयार की गई है। मनपा प्रशासन ने निर्णय लिया है कि अब विद्यार्थियों को लगातार दो शैक्षणिक वर्षों तक मुफ्त यूनिफॉर्म उपलब्ध कराया जाएगा। इस योजना के लिए वर्ष 2026-27 और 2027-28 के लिए कुल 13 करोड़ 33 लाख 49 हजार 472 रुपये का प्रस्ताव तैयार किया गया है, जिसे मंजूरी के लिए महासभा के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। इस पहल का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के बच्चों को शिक्षा से जोड़ना और उन पर पड़ने वाले अतिरिक्त खर्च का बोझ कम करना है। मनपा का मानना है कि इस योजना से विद्यार्थियों की नियमित उपस्थिति बढ़ेगी और शिक्षा

के प्रति उनका उत्साह भी बढ़ेगा। मनपा के शिक्षा विभाग के अनुसार इस योजना का लाभ बालवाड़ी से लेकर दसवीं कक्षा तक के विद्यार्थियों को मिलेगा। वर्तमान में मनपा के विभिन्न स्कूलों में अध्ययनरत 31 हजार से अधिक छात्र-छात्राएं इस योजना के दायरे में आएंगे। प्रत्येक विद्यार्थी को दो जोड़ी यूनिफॉर्म, दो जोड़ी जूते तथा दो जोड़ी मोजे उपलब्ध कराए जाएंगे।

सीएम फडणवीस का आदेश

2027 तक पेयजल करें सुनिश्चित

राज्य में सामान्य से काफी कम बारिश और ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल संकट की आशंका को देखते हुए सरकार ने बड़ा कदम उठाया है

मुंबई: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल बैठक में महाराष्ट्र ग्रामीण पेयजल नीति–2026 को मंजूरी दी गई। साथ ही मुख्यमंत्री ने प्रशासन को अगस्त 2027 तक राज्य में पेयजल उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए ठोस कार्ययोजना तैयार करने का निर्देश दिया है। ग्रामीण पेयजल के लिए निर्धारित नई नीति का उद्देश्य ग्रामीण परिवारों को स्वच्छ, सुरक्षित और नियमित पेयजल उपलब्ध कराना है। इसके तहत जल जीवन मिशन 2.0 की योजनाओं के रखरखाव और मरम्मत के लिए व्यापक ढांचा तैयार किया जाएगा। सरकार गांवों की जल आत्मनिर्भरता बढ़ाने, जलस्रोतों के पुनर्जीवन, वर्षा जल संचयन, अपशिष्ट जल पुनर्चक्रण और जल संरक्षण पर विशेष जोर देगी।

डिजिटल निगरानी और शिकायत निवारण

■ नई नीति के तहत जल योजनाओं की निगरानी के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म, जीआईएस आधारित ट्रैकिंग और केंद्रीय कमांड सेंटर स्थापित किया जाएगा। त्रिस्तरीय शिकायत निवारण प्रणाली भी बनाई जाएगी, जिसमें 'नल जल सेवा' ऐप और 'नल जल मित्र' की मदद ली जाएगी।

कम बारिश ने बढ़ाई चिंता

■ मंत्रिमंडल समीक्षा में सामने आया कि 1 जून से 15 जून के बीच महाराष्ट्र में सामान्य 103.18 मिमी के मुकाबले केवल 27.4 मिमी वर्षा दर्ज हुई, जो सामान्य से काफी कम है। इसी कारण किसानों को फिलहाल जल्दबाजी में बुआई नहीं करने की सलाह दी गई है। सरकार ने मानसून में देरी और जलाशयों में घटते जलस्तर पर भी चिंता जताई।

पाणीपट्टी और रखरखाव पर जोर

■ ग्रामीण जल योजनाओं के रखरखाव के लिए ग्राम पंचायत स्तर पर विशेष निधि बनाई जाएगी। सरकार ने घरेलू जल उपयोग के लिए न्यूनतम 150 रुपए और अधिकतम 400 रुपए मासिक जल शुल्क तय करने को मंजूरी दी है। वसूली में कमी होने पर 15वें और 16वें वित्त आयोग के फंड का उपयोग भी किया जा सकेगा। इससे योजनाओं को लंबे समय तक सुचारु रूप से संचालित रखने में मदद मिलेगी।

महाराष्ट्र विधानमंडल का मॉनसून सत्र

22 जून से 10 जुलाई 2026 तक मुंबई में होगा

मुंबई: महाराष्ट्र राज्य विधानमंडल का मॉनसून सत्र 22 जून से 10 जुलाई, 2026 तक मुंबई में आयोजित किया जाएगा। यह निर्णय विधानसभा और विधान परिषद की कार्य सलाहकार समितियों की बैठक में लिया गया। विधान भवन में हुई इस बैठक में विधान परिषद के सभापति प्रो. राम शिंदे, विधानसभा अध्यक्ष एडवोकेट राहुल नार्वेकर, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजीत पवार, विधानसभा उपाध्यक्ष अन्ना बनसोडे, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा तथा संसदीय कार्य मंत्री चंद्रकांत (दादा) पाटिल और खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री छगन भुजबल शामिल हुए। इनके अलावा विधायक सुधीर मुनगंटीवार, दीपक केसरकर, नाना पटोले, जयंत पाटिल, डॉ. नीलम गोर्हे, अनिल परब, प्रसाद लाड, हेमंत पाटिल, प्रवीण दरेकर, विक्रम काले और सतेज पाटिल के साथ-साथ विधानमंडल सचिव जितेंद्र भोले और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे। बैठक के दौरान मॉनसून सत्र की कार्यवाही की योजना और कार्यक्रम के बारे में विस्तार से चर्चा की गई।

रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का बड़ा ऐलान

अब सिर्फ 48 मिनट में मुंबई से पुणे!

■ भारत खुद बनाएगा अगली बुलेट ट्रेन

मुंबई: भारत में हाईस्पीड रेल नेटवर्क के विस्तार को लेकर एक बड़ी घोषणा हुई है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 17 जून 2026 को जानकारी दी कि देश के अगले बुलेट ट्रेन कॉरिडोर, मुंबई- पुणे मार्ग पर अगले साल 2027 से काम शुरू हो जाएगा। इस प्रोजेक्ट की सबसे खास बात यह है कि इसे भारत खुद अपनी क्षमता से तैयार करेगा, जो तकनीकी आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बड़ा कदम है। वर्तमान में मुंबई और पुणे के बीच की दूरी तय करने में घंटों का समय लगता है, लेकिन बुलेट ट्रेन शुरू होने के बाद 170 किलोमीटर का यह सफर मात्र 48 मिनट में सिमट जाएगा। रेल मंत्री के अनुसार, इस हाईस्पीड कनेक्टिविटी के कारण मुंबई और पुणे ट्विन सिटी बन जाएंगे, जिससे आर्थिक और सांस्कृतिक आदानप्रदान को बढ़ावा मिलेगा। अश्विनी वैष्णव ने स्पष्ट किया कि जहां मुंबईअहमदाबाद कॉरिडोर का निर्माण जापान के सहयोग से किया जा रहा है, वहीं मुंबई–पुणे कॉरिडोर का निर्माण भारत स्वयं करेगा। उन्होंने कहा कि अब देश के पास बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट्स को स्वतंत्र रूप से संभालने की क्षमता है। यह प्रोजेक्ट उन 7 नए हाईस्पीड रेल कॉरिडोर का हिस्सा है जिनकी घोषणा बजट 202627 में की गई थी। इस नई रेल परियोजना का उद्देश्य केवल यातायात सुगम बनाना नहीं, बल्कि एक मजबूत आर्थिक गलियारा तैयार करना है। रेल मंत्री के मुताबिक, जब मुंबई, पुणे, हैदराबाद, अहमदाबाद, सूरत, वापी और ठाणे जैसे शहर बुलेट ट्रेन से जुड़ेंगे, तो यह पूरे क्षेत्र के लिए एक बड़ा आर्थिक इकोसिस्टम तैयार करेगा। इसके अलावा, पुणे–हैदराबाद के बीच 500 किमी की दूरी भी बुलेट ट्रेन के जरिए मात्र 2 घंटे 8 मिनट में पूरी की जा सकेगी।

महाराष्ट्र में ड्रोन, रोबोटिक्स इंडस्ट्री को मिलेगा बढ़ावा

कैबिनेट ने मानव रहित प्रणाली नीति–2026 को दी मंजूरी

मुंबई: महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में ड्रोन, रोबोटिक्स और स्वायत्त वाहनों के निर्माण को गति देने के लिए 'महाराष्ट्र मानव रहित प्रणाली नीति–2026' को हरी झंडी दे दी है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में इस दूरगामी नीति को मंजूरी दी गई। इस नीति का मुख्य उद्देश्य अनुसंधान, विकास, उत्पादन और रखरखाव के क्षेत्रों में स्वयंचलित प्रणालियों को मजबूत करना है, जिससे महाराष्ट्र इस आधुनिक तकनीक का अग्रणी केंद्र बन सके। इस नीति के माध्यम से राज्य के औद्योगिक परिदृश्य में क्रांतिकारी बदलाव आने की उम्मीद है। सरकार का लक्ष्य इस क्षेत्र में लगभग 25 हजार करोड़ रुपए का भारी निवेश आकर्षित करना है। इसके साथ ही, युवाओं के लिए एक लाख से अधिक प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसरों का सृजन होगा। यह नीति आगामी पांच वर्षों या नई नीति आने तक प्रभावी रहेगी।

कृषि, सुरक्षा और लॉजिस्टिक्स में बड़ा बदलाव

■ महाराष्ट्र की नई मानव रहित प्रणाली नीति के तहत ड्रोन, रोबोटिक्स और अन्य स्वायत्त तकनीकों का उपयोग कृषि, सुरक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन और लॉजिस्टिक्स जैसे क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर किया जाएगा। इन तकनीकों की मदद से फसलों पर कीटनाशक और उर्वरकों का छिड़काव अधिक सटीक और कम समय में किया जा सकेगा। वहीं, बुनियादी ढांचे की निगरानी, आपदा प्रबंधन, ड्रोन एम्बुलेंस सेवाएं और गोदामों के स्वचालन जैसे कार्य भी अधिक प्रभावी बनेंगे। सरकार का मानना है कि कठिन, जोखिमपूर्ण और दुर्गम क्षेत्रों में इन प्रणालियों का उपयोग मानव श्रम पर निर्भरता कम करेगा तथा कार्यों की गति, सुरक्षा और दक्षता में उल्लेखनीय वृद्धि करेगा।

महिलाओं को ड्रोन पायलट का विशेष प्रशिक्षण

■ राज्य में तकनीकी कौशल को बढ़ावा देने के लिए तीन उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए जाएंगे, जहां 5,000 रिमोट पायलट तैयार करने पर जोर होगा। विशेष रूप से 'नमो ड्रोन दीदी' योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के तहत स्वयं सहायता समूहों की 1,000 से अधिक महिलाओं को प्रमाणित ड्रोन पायलट के रूप में प्रशिक्षित किया जाएगा। उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए सरकार बिजली सब्सिडी, जीएसटी रिफंड और स्टैंप ड्यूटी में छूट जैसे वित्तीय लाभ भी देगी।

मानसून में बढ़ता संक्रमण खतरा, इम्यूनिटी मजबूत रखने की सलाह

■ डॉ. आशीष मिश्रा
श्रीराम पॉलिक्लिनिक व आयुर्वेदिक दवाखाना

बारिश का मौसम जहां एक ओर गर्मी से राहत देता है, वहीं दूसरी ओर यह अपने साथ कई तरह की स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियां भी लेकर आता है। इस दौरान वातावरण में नमी और उमस का स्तर काफी बढ़ जाता है, जिससे बैक्टीरिया, वायरस, फंगस और अन्य सूक्ष्म जीव तेजी से पनपने लगते हैं। इसका सीधा असर मानव स्वास्थ्य पर पड़ता है और संक्रमण का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। विशेषकर कमजोर इम्यूनिटी वाले लोग इस मौसम में जल्दी बीमारियों की चपेट में आ जाते हैं। सर्दी-जुकाम, वायरल बुखार, पेट संक्रमण और त्वचा संबंधी समस्याएं मानसून में आम हो जाती हैं। ऐसे में डॉक्टर का मानना है कि इस मौसम में शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी को मजबूत रखना बेहद जरूरी होता है। डॉक्टर के अनुसार, मजबूत इम्यून सिस्टम शरीर को बाहरी संक्रमणों से बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगर इम्यूनिटी अच्छी हो तो शरीर बैक्टीरिया और वायरस से बेहतर

तरीके से लड़ सकता है और बीमारियों का खतरा कम हो जाता है। इसी को ध्यान में रखते हुए डॉक्टर मानसून के दौरान कुछ विशेष आहार को डाइट में शामिल करने की सलाह देते हैं, जिन्हें 'सुपर फूड्स' कहा जाता है। इन खाद्य पदार्थों में ऐसे पोषक तत्व होते हैं जो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में मदद करते हैं। इस मौसम में हल्दी, अदरक और तुलसी जैसे प्राकृतिक औषधीय गुणों वाले पदार्थ बेहद फायदेमंद माने जाते हैं। हल्दी में मौजूद करक्यूमिन शरीर में सूजन कम करने और संक्रमण से लड़ने में मदद करता है। वहीं अदरक पाचन तंत्र को मजबूत बनाता है और सर्दी-जुकाम से बचाव करता है। इसके अलावा विटामिन-सी से भरपूर फल जैसे नींबू, संतरा और आंवला भी इम्यूनिटी बढ़ाने में सहायक होते हैं। ये शरीर में एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा को बढ़ाते हैं, जिससे रोगों से लड़ने की क्षमता मजबूत होती है। प्रोबायोटिक युक्त खाद्य पदार्थ जैसे दही भी मानसून में लाभकारी माने जाते हैं, क्योंकि यह पेट के अच्छे बैक्टीरिया को बढ़ाते हैं और पाचन तंत्र को स्वस्थ रखते हैं। साथ ही हल्का और ताजा भोजन करने की सलाह भी दी जाती है ताकि शरीर पर अतिरिक्त दबाव न पड़े। डॉक्टर यह भी सलाह देते हैं कि इस मौसम में बाहर के खुले और अस्वच्छ भोजन से बचना चाहिए, क्योंकि इससे संक्रमण का खतरा बढ़ सकता है। साफ पानी का सेवन और व्यक्तिगत स्वच्छता का ध्यान रखना भी बेहद जरूरी है। कुल मिलाकर, मानसून का मौसम जहां एक ओर राहत लेकर आता है, वहीं दूसरी ओर यह स्वास्थ्य के लिए चुनौतियां भी पैदा करता है। ऐसे में सही खान-पान और मजबूत इम्यूनिटी के जरिए इन बीमारियों से बचा जा सकता है और स्वस्थ जीवन का आनंद लिया जा सकता है।

'यह परिशिष्ट किसी एक मत या संप्रदाय का प्रचार नहीं, बल्कि मानवता, नैतिकता, आध्यात्मिकता और सहअस्तित्व के सार्वभौमिक मूल्यों का मंच है।'

'आध्यात्मिक संवाद'

श्रीमद्भगवद्गीता से समझें जीवन की कठिनाइयों का अर्थ

'यतो धर्मस्ततो जयः' अर्थात जहां धर्म है, वहां विजय निश्चित है। सनातन संस्कृति और भारतीय शास्त्रों में इस सिद्धांत का गहरा उल्लेख मिलता है। इसके अनुसार धर्म और सत्य के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति अंततः विजय प्राप्त करता है। लेकिन दैनिक जीवन के अनुभव कई बार इस विचार से अलग दिखाई देते हैं, जहां ईमानदारी और सच्चाई के मार्ग पर चलने वाले लोगों को अधिक संघर्ष, दुख और मानसिक तनाव का सामना करना पड़ता है। कई लोग यह प्रश्न करते हैं कि जब धर्म का मार्ग सही माना जाता है, तो फिर उस पर चलने वाले व्यक्ति को कठिनाइयों का सामना क्यों करना पड़ता है। विशेषज्ञों और आध्यात्मिक विचारकों के अनुसार, यह स्थिति जीवन के कर्म और समय के गहरे सिद्धांत से जुड़ी हुई है। श्रीमद्भगवद्गीता में भगवान श्रीकृष्ण ने कर्म और परिणाम के बीच के संबंध को विस्तार से समझाया है। गीता के अनुसार व्यक्ति का कर्तव्य केवल कर्म करना है, जबकि उसके फल की चिंता करना आवश्यक नहीं है। धर्म के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति कई बार तात्कालिक रूप से कठिन परिस्थितियों का

सामना करता है, लेकिन दीर्घकाल में वही मार्ग उसे स्थिरता और सच्ची सफलता की ओर ले जाता है। विशेषज्ञों का मानना है कि ईमानदार व्यक्ति अक्सर तात्कालिक लाभ या अनुचित तरीकों से समझौता नहीं करता, जिसके कारण उसे समाज में संघर्ष करना पड़ सकता है। वहीं दूसरी ओर, अनैतिक तरीकों से चलने वाले लोग कभी-कभी जल्दी सफलता प्राप्त करते दिख सकते हैं, लेकिन वह स्थायी नहीं होती। गीता का संदेश यह भी है कि जीवन में मिलने वाले सुख और दुख दोनों ही अस्थायी हैं। व्यक्ति को अपने कर्तव्य और धर्म पर स्थिर रहकर आगे बढ़ना चाहिए। यह मार्ग कठिन अवश्य हो सकता है, लेकिन यही आत्मिक शांति और वास्तविक विजय की ओर ले जाता है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो दुख और संघर्ष व्यक्ति के चरित्र को मजबूत बनाने का कार्य करते हैं। कठिन परिस्थितियां ही व्यक्ति को धैर्य, सहनशीलता और आत्मविश्वास सिखाती हैं। इसलिए धर्म के मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति के जीवन में आने वाली चुनौतियों को केवल नकारात्मक रूप में नहीं देखा जाना चाहिए।

आज के समय में भी कई लोग इस विचार को अपने जीवन में अपनाते हैं कि ईमानदारी भले ही कठिन हो, लेकिन उसका परिणाम दीर्घकाल में सकारात्मक ही होता है। यह सोच समाज में विश्वास और नैतिक मूल्यों को मजबूत करती है। इस प्रकार, गीता का संदेश स्पष्ट करता है कि धर्म के मार्ग पर चलना आसान नहीं होता, लेकिन वही मार्ग अंततः सच्ची सफलता, आत्मिक शांति और स्थायी विजय की ओर ले जाता है।

पंचामृत का महत्वः क्यों माना जाता है इसे अमृत के समान पवित्र ?

सनातन धर्म में पूजा-पाठ, यज्ञ, अभिषेक और विभिन्न धार्मिक अनुष्ठानों में पंचामृत का विशेष महत्व बताया गया है। धार्मिक और पौराणिक मान्यताओं के अनुसार पंचामृत केवल एक पवित्र मिश्रण नहीं, बल्कि शुभता, पवित्रता और दिव्य ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। 'पंचामृत' शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है 'पंच' अर्थात पांच और 'अमृत' अर्थात अमरत्व प्रदान करने वाला दिव्य रस। इसमें सामान्यतः दूध, दही, घी, शहद और शक्कर या मिश्री का मिश्रण तैयार किया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार समुद्र मंथन के समय अनेक दिव्य रत्नों के साथ अमृत कलश भी प्रकट हुआ था। पंचामृत को उसी अमृत का प्रतीक माना जाता है। इसी कारण पूजा-अर्चना और देव अभिषेक में इसका उपयोग अत्यंत शुभ माना गया है। पुराणों में वर्णित है कि भगवान विष्णु, भगवान शिव, श्रीकृष्ण तथा अन्य देवी-देवताओं के अभिषेक में पंचामृत का प्रयोग करने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है।

पंच तत्वों का प्रतीक : पंचामृत में प्रयुक्त पांचों पदार्थों को जीवन के पांच महत्वपूर्ण गुणों का प्रतीक माना गया है। दूध पवित्रता और सात्विकता

का, दही समृद्धि और स्वास्थ्य का, घी तेज एवं शक्ति का, शहद मधुरता और एकता का तथा मिश्री सुख और आनंद का प्रतीक माना जाता है। इन पांचों तत्वों का संगम जीवन में संतुलन और सकारात्मकता का संदेश देता है।

देव अभिषेक में पंचामृत का प्रयोग : मंदिरों और घरों में होने वाली पूजा के दौरान देवी-देवताओं का अभिषेक पंचामृत से किया जाता है। विशेष रूप से शिवलिंग, श्रीकृष्ण, भगवान विष्णु और गणेशजी के अभिषेक में इसका उपयोग अत्यंत शुभ माना गया है। धार्मिक मान्यता है कि पंचामृत से अभिषेक करने पर भगवान प्रसन्न होते हैं और भक्तों पर अपनी कृपा बरसाते हैं।

पेज-1 का शेष

पीएम नरेंद्र मोदी से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कर दिया बड़ा वादा...

ट्रंप ने मोदी को ऐसा नेता बताया जो बाहर से शांत नजर आते हैं, लेकिन निर्णय लेने और बातचीत के समय बेहद दृढ़ रहते हैं। उन्होंने कहा कि मोदी की नेतृत्व क्षमता की वजह से भारत लगातार आगे बढ़ रहा है और भविष्य में भी प्रगति करता रहेगा।

भारतीय नाविकों की मौत पर क्या कहा गया ?

बैठक के दौरान हाल ही में होर्मुज जलडमरूमध्य क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य कार्रवाई के दौरान मारे गए तीन भारतीय नाविकों का मुद्दा भी उठा। इस पर ट्रंप ने दुख जताते हुए कहा कि उन्हें इस घटना की जानकारी है। उन्होंने कहा कि मैंने इसके बारे में सुना है। यह बहुत कठिन पेशा है। हम इस पर काम कर रहे हैं। ट्रंप की यह टिप्पणी उन परिवारों के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है जो इस घटना से प्रभावित हुए हैं।

जीडीपी का छह प्रतिशत शिक्षा पर खर्च हो : संसदीय समिति...

समिति ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 का उल्लेख करते हुए कहा कि इसमें केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा शिक्षा में सार्वजनिक निवेश बढ़ाकर जीडीपी का छह प्रतिशत तक पहुंचाने की स्पष्ट परिकल्पना की गई है। समिति ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के 16 जून 2024 के उस बयान का समर्थन किया, जिसमें उन्होंने कहा था कि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) में काफी सुधार की आवश्यकता है। समिति ने एनटीए से राधाकृष्णन समिति की सिफारिशों को शीघ्र लागू करने को कहा है। रिपोर्ट के अनुसार, संसदीय समिति ने यह भी सिफारिश की कि उच्च शिक्षा विभाग और एनटीए सभी हितधारकों के साथ व्यापक स्तर पर अतिरिक्त परामर्श करें और देशव्यापी प्रतियोगी परीक्षाओं के दोषरहित संचालन के लिए एक प्रोटोकॉल तैयार करें।

जुलाई से लागू होगा भारत-ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौता...

वहीं, वास्तविक मजदूरी में 2.2 अरब पाउंड का इजाफा होने का अनुमान है। इसके अलावा भारत और ब्रिटेन के बीच द्विपक्षीय व्यापार हर साल 25.5 अरब पाउंड तक बढ़ सकता है। ब्रिटेन भी भारत से आने वाले कई उत्पादों पर शुल्क कम करेगा। इसमें कपड़े, जूते-चप्पल और कुछ खाद्य उत्पाद शामिल हैं।

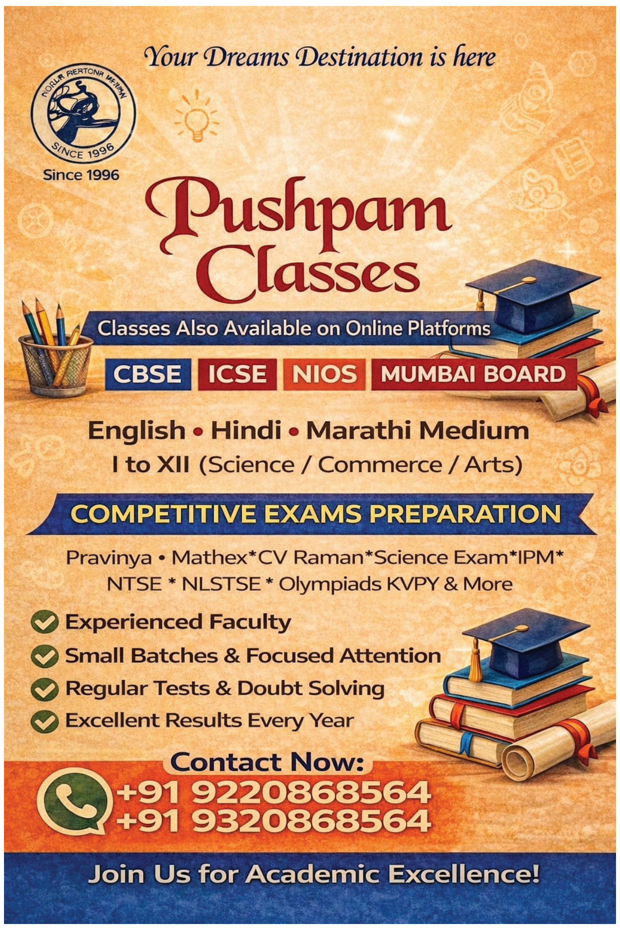

विशेषविश्लेषणम्

भारत-नेपालयोः सम्बन्धयोः नूतनः अध्यायः

किं सीमाविवादस्य समाधानस्य मार्गे अग्रे सरतः उभौ अपि मित्रराष्ट्रे?

भारत-नेपालयोः सम्बन्धः केवलं द्वयोः समीपवर्तिनोः राष्ट्रयोः सम्बन्धः नास्ति, अपितु सः सहस्रवर्षपरम्परया संयुक्तः सांस्कृतिकः, धार्मिकः, ऐतिहासिकः, सामाजिकश्च बन्धः अस्ति। प्रायः १८५० किलोमीटर-परिमिता मुक्तसीमा, तथाकथितः 'रोटी-बेटी-सम्बन्धः', समानधार्मिकपरम्परा तथा दीर्घकालप्रचलिता मैत्रीसन्धिः एतं सम्बन्धं विश्वे विशिष्टतमं करोति।

तथापि गतवर्षेषु कालापानी-लिपुलेख-लिम्पियाधुरा-प्रदेशानामधिकारे विषयः भारत-नेपालयोः मध्ये चचार्याः केन्द्रबिन्दुः अभवत्। २०२० तमे वर्षे नेपालदेशेन नूतनः राजनैतिकः मानचित्रः प्रकाशितः, यस्मिन् एते प्रदेशाः नेपालस्य भागत्वेन प्रदर्शिताः। ततः आरभ्य सीमाविवादः अधिकं चर्चितोऽभवत्। भारतेन तदेकपक्षीयं निर्णयं मन्यते, यदा नेपालदेशः ऐतिहासिकदस्तावेजानां सुगौली-सन्धेः च स्वव्याख्यानस्य आधारेण स्वदावान् प्रस्तौति।

अधुना जूनमासे २०२६ तमे वर्षे नेपालस्य प्रधानमन्त्री बालेन्द्रशाह-महोदयस्य भारतयात्रया नूतनसंवादस्य सम्भावनाः उद्भूताः। नवीनदिल्ली-नगरे तेन उक्तं यत् 'एकोनविंशतितमशताब्द्याः विवादाः एकविंशतितमशताब्द्याः दृष्ट्या एव समाधातव्याः'-इति। एषः वक्तव्यः उभयोः राष्ट्रयोः मध्ये विश्वासपुनर्निर्माणस्य

शुभसंकेतत्वेन दृष्टः।

अस्य विवादस्य मूलं १८१६ तमे वर्षे सम्पन्नायाः सुगौली-सन्धेः तथा कालीनद्याः वास्तविकोद्गमस्थानस्य निर्धारणेन सम्बद्धम् अस्ति। भारतं नेपालश्च स्वस्वपक्षे ऐतिहासिकमानचित्राणि, प्रशासकीयाभिलेखान्, प्राचीनदस्तावेजांश्च प्रमाणरूपेण प्रस्तौतः। अतः विशेषज्ञानां मतम् अस्ति यत अस्य समस्यायाः समाधानं केवलं राजनैतिकघोषणाभिः न सम्भवति, किन्तु संयुक्तसर्वेक्षणेन, ऐतिहासिक-अध्ययनेन, पारदर्शिन्या वार्तया च एव साध्यम्।

अस्मिन् सम्पूर्णे प्रसङ्गे नेपालदेशे चीनदेशस्य वर्धमानः प्रभावोऽपि चचार्याः विषयः जातः। निवेशक्षेत्रे, आधारभूतसंरचनायां, राजनैतिकक्षेत्रे च चीनस्य सक्रियतां प्रति बहवः विश्लेषकाः चिन्तां प्रकटयन्ति। तथापि नेपालदेशः पुनः पुनः प्रतिपादयति यत् सः स्वातन्त्र्यपूर्णां विदेशनीतिमनुसृत्य निर्णयान् करोति।

भारतदेशः अपि बहुवर्षेभ्यः नेपालस्य विकासयात्रायां सहयोगी राष्ट्ररूपेण स्थितः अस्ति। भूकम्प-आपदासहायतायाः आरभ्य शिक्षाक्षेत्रे, स्वास्थ्यसेवायां, ऊर्जा-परियोजनासु, अधोसंरचनाविकासे च उभयोः राष्ट्रयोः सहयोगः निरन्तरं वर्धमानः दृश्यते। विशेषज्ञानां मते यदि संयुक्तसीमायोगः, वैज्ञानिकसर्वेक्षणम्, सीमाहाटव्यवस्था, डिजिटल-संयोजनम्, नियमित-उच्चस्तरीय-वार्ताश्च प्रभावी रूपेण प्रवर्तिताः स्युः, तर्हि सीमाविवादस्य समाधानदिशि सार्थका प्रगतिः सम्भाव्या अस्ति।

अन्ततः भारत-नेपालयोः सम्बन्धः केवलं मानचित्रस्य रेखाभिः परिमेयः नास्ति। इतिहासः, संस्कृतिः, धर्मः, जनजीवनम्, पारिवारिकसम्बन्धाश्च एतौ राष्ट्रौ गाढतया सम्बध्नन्ति। अतः सीमाविवादस्य स्थायिसमाधानं केवलं भौगोलिकप्रश्नस्य समाधानं न, अपितु परस्परविश्वासस्य, संवादस्य, साझा-परम्परायाः च संरक्षणम् अपि अस्ति।

भारत-नेपालयोः समक्षं प्रमुखा चुनौती सीमा-निर्धारणस्य नास्ति, अपितु परस्परविश्वासस्य अधिकसुदृढीकरणस्य अस्ति। यदि वर्तमानसंवादप्रक्रिया अग्रे सरति, तर्हि सा केवलं सीमाविवादस्य समाधानमार्गं न उद्घाटयिष्यति, अपितु दक्षिण-एशियाक्षेत्रे सहयोगस्य, स्थैर्यस्य, सौहार्दस्य च नूतनं आदर्शमपि स्थापयिष्यति।

प्यूपिल्स टाइम्स विशेष-टिप्पणी

कन्या किं विकल्पमात्रम्?

भ्रूण-लिङ्ग-परीक्षणम् : प्रौद्योगिक्याः अपेक्षया सामाजिक-चेतनायाः प्रश्नः

विज्ञानेन मानवजीवनाय अनेकाः महत्त्वपूर्णाः उपलब्धयः प्रदत्ताः। गर्भस्थ-शिशोः स्वास्थ्य-परीक्षणम् अपि तासु प्रमुखम् अस्ति। किन्तु यदा एषा एव प्रौद्योगिकी भ्रूणस्य लिङ्ग-निर्धारणस्य तदाधारित-निर्णयानां च साधनं भवति, तदा विषयः केवलं चिकित्साशास्त्रस्य न भवति, अपितु समाजस्य नैतिक-चेतनायाः प्रश्नः भवति। भारते भ्रूण-लिङ्ग-परीक्षणस्य दुरुपयोगं निरोद्धुं कठोराः वैधानिक-व्यवस्थाः प्रवर्तिताः। तासां उद्देश्यं विज्ञानस्य विरोधः न, अपितु पुत्र-प्राधान्येन कन्यायाः अवमूल्यनं कुर्वन्तीं सामाजिक-मानसिकतां नियन्त्रयितुम् आसीत्। चीनदेशे अपि पूर्वकाले लिङ्ग-असन्तुलनस्य समस्या दृष्टा, यस्य परिणामस्वरूपं नियन्त्रणात्मकाः नीतयः स्वीकृताः। एतत् दर्शयति यत् समस्या केवलं कानूनी नास्ति, अपितु सामाजिकापि अस्ति।

भ्रूण-लिङ्ग-परीक्षणविमर्शस्य प्रमुख-आयामाः
४०%-कन्या-भ्रूण-संरक्षणम्
२५%-प्रजनन-अधिकारः तथा गोपनीयता
२०%-जनसंख्या-सन्तुलनम्
१०%-चिकित्सकीय-नैतिकता
५%-राजनैतिक-विमर्शः

टिप्पणीः एतत् वितरणं सांकेतिकम् अस्ति; न तु कस्यचित् सांख्यिकीय-अध्ययनस्य परिणामः।

गर्भस्था कन्या न कस्यचित् गणनायाः विषयः, न च सामाजिक-पूर्वाग्रहस्य वस्तु। सा जीवनस्य सम्भावना, मानवतायाः गौरवम्, भविष्यस्य च आधारशिला अस्ति। विज्ञानं लिङ्गं ज्ञापयितुं शक्नोति, किन्तु जीवनस्य मूल्यं निर्धारयितुं न शक्नोति। अतः प्रश्नः अयं न यत् कः देशः लिङ्ग-ज्ञानस्य अनुमतिं ददाति, कः वा न ददाति। वास्तविकः प्रश्नः न केवलं लिङ्गस्य ज्ञानस्य अस्ति, अपितु अस्य अस्ति यत् वयं गर्भस्थ-जीवनस्य मूल्यं कथं पश्यामः। यः समाजः कन्यां समानगौरवेण स्वीकरोति, स एव वास्तविकरूपेण सभ्यः प्रगतिशीलश्च कथ्यते।

संघ-कार्यालये आक्रमणस्य निष्पक्ष-अन्वेषणं कठोर-कार्यवाही च अपेक्षिता

विश्वहिन्दू-परिषदः सेवा-विभागस्य प्रान्तीय-प्रवक्ता संजय-सर्राफ-महोदयः राँची-स्थिते राष्ट्रीय-स्वयंसेवक-संघस्य कार्यालये जातस्य कथित-विस्फोटक-आक्रमणस्य तीव्रां निन्दां कृतवान्। तेनोक्तं यत् एषा घटना लोकतान्त्रिक-मूल्यानां सामाजिक-सौहार्दस्य च विरुद्धः गम्भीरः प्रहारः अस्ति। तस्य मते एतादृशाः घटनाः समाजे असुरक्षायाः वातावरणं जनयन्ति तथा च विधि-व्यवस्थायाः स्थितौ प्रश्नचिह्नम् आरोपयन्ति।

सः अवदत् यत् एषा घटना राज्ये वर्धमानानाम् आपराधिक-क्रियाकलापानाम् तथा सुरक्षा-व्यवस्थायाः चुनौत्याः अपि प्रकाशयति। संजय-सर्राफ-महोदयेन झारखण्ड-शासनात् अस्य प्रकरणस्य निष्पक्षं पारदर्शि च शीघ्रं अन्वेषणं सुनिश्चितं कर्तुम् आग्रहः कृतः। तेन दोषिणां शीघ्रं परिचयं कृत्वा तेषां विरुद्धं कठोर-वैधानिक-कार्यवाही कर्तव्या इति अपि उक्तम्। प्रशासनं प्रति अपि तेन शान्तेः, सुरक्षायाः तथा सामाजिक-विश्वासस्य संरक्षणार्थं प्रभाविकाणि पदानि स्वीकर्तुम् आह्वानं कृतम्।

कोडरमाजनपदस्य केसरिय-कलाकन्दाय जीआई-चिह्नम्

प्रादेशिक-विशिष्टतायाः वैश्विकी मान्यता

झारखण्डराज्यस्य कोडरमाजनपदस्य प्रसिद्धः केसरिय-कलाकन्दः भौगोलिक-सूचकाङ्क-चिह्नम् (जीआई-टैग) प्राप्तवान्। अनेन अस्य पारम्परिक-मिष्टान्नस्य विशिष्टा पहचानः राष्ट्रीय-अन्तरराष्ट्रीयस्तरे अधिकं प्रतिष्ठां प्राप्स्यति। तस्य च निमार्णे संलग्नानां स्थानीय-शिल्पिनां व्यापारिणां च विशेषः लाभः भविष्यति।

झुमरी-तिलैया-प्रदेशे बहुवर्षेभ्यः निर्मीयमाणः अयं कलाकन्दः स्वस्य विशिष्ट-स्वादेन, केसरयुक्त-वर्णेन तथा पारम्परिक-निर्माण-पद्धत्या प्रसिद्धिम् अर्जितवान्। जीआई-चिह्नस्य प्राप्त्या अस्य मिष्टान्नस्य वैधानिकं संरक्षणं सुनिश्चितं भविष्यति, येन कृत्रिम-उत्पादानां प्रसारः निरुद्धः भविष्यति तथा वास्तविक-निमार्तृभ्यः समुचितः लाभः प्राप्स्यति। उल्लेखनीयमस्ति यत् एतत् कोडरमाजनपदस्य प्रथमं जीआई-चिह्नम् अस्ति। तेन झारखण्डस्य सांस्कृतिक-खाद्य-परम्परायाः गौरवं वर्धितम्। एषा उपलब्धिः स्थानीय-अर्थव्यवस्थां सुदृढां करिष्यति तथा कोडरमाजनपदस्य ख्यातिं देशे विदेशे च अधिकां विस्तारयिष्यति।

त्विषा-शर्मा-मृत्युप्रकरणे

गिरिबाला-सिंह-समर्थसिंहयोः न्यायिकाभिरक्षा ३० जूनपर्यन्तं विस्तृता

पूर्वाभिनेत्र्याः त्विषा-शमार्याः संदिग्ध-मृत्युसम्बद्धे चर्चिते प्रकरणे भोपाल-जनपद-न्यायालयेन गिरिबाला-सिंहस्य तस्याः पुत्रस्य च समर्थसिंहस्य न्यायिकाभिरक्षा ३० जूनपर्यन्तं विस्तृता। मङ्गलवासरे सम्पन्नायां न्यायालयीय-श्रवणप्रक्रियायाम् उभावपि आरोपितौ भोपाल-केन्द्रीय-कारागारात् दृश्यश्रव्य-माध्यमेन न्यायालयस्य समक्षम् उपस्थापितौ। एतस्य प्रकरणस्य अन्वेषणं केन्द्रीय-अन्वेषण-ब्यूरो-संस्था (सीबीआई) करोति। संस्थया न्यायिकाभिरक्षावृद्धेः अनुरोधः कृतः, यं न्यायालयेन अनुमोदितम्। अधुना सीबीआई-संस्थया सिंह-परिवारस्य निवासस्थाने घटनाक्रमस्य पुनर्निर्माणम् अपि सम्पन्नम्। उल्लेखनीयमस्ति यत गतस्य मे-मासस्य १२ दिनाङ्के त्विषा-शर्मा भोपाल-नगरे स्वस्य श्वशुरगृहे मृतावस्थायां प्राप्ता आसीत्। प्रकरणस्य अन्वेषणं अद्यापि प्रवर्तमानम् अस्ति।

ऑपरेशन टाइगर' इति विषयेन महाराष्ट्र-राजनीत्यां तीव्रा चर्चा

शिवसेना (यूबीटी) दले विभाजनस्य कयासाः

महाराष्ट्रस्य राजनीत्यां सम्प्रति 'ऑपरेशन टाइगर' इति विषयः व्यापकचचार्याः केन्द्रबिन्दुः जातः अस्ति। शिवसेना (शिन्दे-गुटस्य) नेता कृपाल-तुमाने-महोदयेन कृतं वक्तव्यं राजनीतिक-मण्डलेषु विशेषां चर्चाम् अजनयत्। तेन उक्तं यत् शिवसेना (यूबीटी) दलस्य अनेकाः लोकसभा-सांसदाः तथा केचन विधायकाः मुख्यमन्त्रिणः एकनाथ-शिन्दे-महोदयस्य सम्पर्के सन्ति। अधुना घटनाविकासः नूतनां दिशं प्राप्तवान्। विविध-माध्यम-प्रतिवेदनानुसारं शिवसेना (यूबीटी) दलस्य षट् सांसदाः पृथकसंसदीय-समूहस्य गठनाय प्रयत्नशीलाः सन्ति तथा लोकसभा-अध्यक्षाय पत्रमपि प्रेषितमिति वार्ताभिः एते

कयासाः अधिकं बलं प्राप्तवन्तः। अपरपक्षे उद्धव-ठाकरे-गुटेन एते सर्वे दावाः निरस्ताः। राज्यसभा-सांसदः संजय-राउत-महोदयः आरोपितवान् यत् दलस्य सांसदानां प्रति राजनैतिक-प्रभावः प्रयुज्यते। तेन स्पष्टतया उक्तं यत् शिवसेना (यूबीटी) दलम् अद्यापि संगठितम् अस्ति तथा विपक्षः जनमानसे भ्रमं प्रसारयितुं प्रयतते।

राजनीतिक-विश्लेषकाणां मते, यदि एताः दलबदल-सम्भावनाः वास्तविकतां प्राप्नुयुः, तर्हि महाराष्ट्रस्य राजनीत्यां शक्तिसन्तुलनम् प्रभावितं भवेत्। सम्प्रति सर्वेषां दृष्टिः भाविषु राजनीतिक-घटनाविकासेषु तथा लोकसभा-अध्यक्षस्य निर्णयस्य उपरि केन्द्रिता अस्ति।

नॉर्वे-राजपरिवारसम्बद्धे चर्चिते प्रकरणे महत्त्वपूर्णो निर्णयः

युवराज्ञ्याः पुत्रः चतुर्वर्षीय-कारावासदण्डेन दण्डितः

नॉर्वे-देशस्य राजधानी ओस्लो-नगरे स्थितेन न्यायालयेन राजपरिवारसम्बद्धे चर्चिते प्रकरणे युवराज्ञ्याः मेटे-मेरिट-महोदयायाः पुत्रः मारियुस्-बोर्ग्-होइबी द्वयोः बलात्कार-प्रकरणयोः दोषी इति निर्णीय चतुर्वर्षीयेन कारावासदण्डेन दण्डितः। अभियोजनपक्षस्य कथनानुसारं वर्षेषु २०१८ तः २०२४ पर्यन्तं तेन अनेकासां महिलानां यौन-शोषणं कृतम्, यासु काश्चन अल्पवयस्काः अपि आसन्। प्रस्तुतसाक्ष्याणां साक्षिणां च कथनानाम् आधारेण न्यायालयेन सः दोषी इति निरूपितः।

मारियुस्-बोर्ग्-होइबी इत्यस्य पालन-पोषणं नॉर्वे-राजपरिवारस्य परिवेशे अभवत्। सः युवराज्ञ्या मेटे-मेरिट-महोदयया युवराजेन हाकोन्-महोदयेन च सह राजप्रासादे वर्धितः। तथापि तस्य कापि आधिकारिक-राजकीय-उपाधिः संवैधानिक-अधिकारो वा नासीत्। अस्मिन् निर्णये नॉर्वे-देशे व्यापकः जनविमर्शः समुत्पन्नः।

Indian Army receives 106 Agniveg suicide drones

Capable of attacking targets up to 180 km inside

New Delhi: Indigenous defense technology company SMPP has handed over 106 turbojet engine-equipped Peacekeeper (Agniveg) suicide drones to the Army. These drones are capable of penetrating 180 kilometers inside enemy territory and carrying out precise attacks on targets. The defense company said that the operational range of the drone is up to 180 kilometers and its maximum speed is 450 kilometers per hour. It can autonomously launch precision strikes on military structures, logistics hubs, command centres, radar stations and other strategic targets. It can continue its mission despite attempts like jamming and spoofing. The company has completed the supply of 100 operational drones and 6 training drones to the Army. This is an important step towards India's unmanned warfare capability and self-reliance in the defense sector.

Was successful in achieving every goal

The defense company said that during the trials, the drone achieved a circular error probable (CEP) of less than five meters even in heavy jamming and spoofing environments. This proved its accuracy and reliability. The system bridges the capability gap between conventional artillery and long-range missiles and gives troops a new option to deliver rapid and accurate strikes against time-sensitive targets.

Pitch black maneuvers

Indian Air Force will show bravery

More than 100 fighter planes from 19 countries will be involved

New Delhi: The Air Force is once again ready to prove its strength in the Indo-Pacific region. The Air Force is going to participate in the international air exercise Pitch Black-2026 to be held from July 20 to August 7 in Darwin, Australia. During this time, the Air Force with its brave pilots and state-of-the-art fighter planes will show its strength in front of 18 other friendly countries of the world. More than 100 fighter and transport aircraft and hundreds of military personnel from 19 countries will participate in this exercise. Its main objective is to strengthen mutual coordination and combat capability in complex and war-like situations. This exercise is extremely important for the stability and security of the Indo-Pacific region. Major countries participating in the Pitch Black exercise will include India, Brunei, Canada, Fiji, Finland, France, Indonesia, Japan, Malaysia, New Zealand, Papua New Guinea, Philippines, South Korea, Singapore, Spain, Sweden, Thailand, United Kingdom and the US. During the maneuvers, a Middle Beach Flying Display will be organized on July 23 for local citizens and aviation lovers. During this time, people will be able to see the amazing stunts of fighter planes in the sky from 5 to 6:30 pm. Also, on August 1, the general public will get a chance to see military aircraft and equipment closely and meet the brave pilots.

Hence the name pitch black: A large part of this exercise is conducted at night, so that the pilots can become adept at aiming accurately and engaging the enemy even in extremely difficult conditions. That is why it is named pitch black. During the exercise, strategic proxy war in the sky, both offensive and defensive air combat is practiced.

Mahajugalbandi of 19 countries: More than 100 fighter and transport aircraft and thousands of military personnel from 19 countries around the world are taking part in this international air exercise. Its primary objective is to strengthen coordination, shared strategy and operational capability among the air forces of allied countries in highly complex and realistic war-like situations. This exercise is being considered very important for the security and stability of the Indo-Pacific region. Apart from India, major countries like America, Britain, France, Japan, Australia, Indonesia, South Korea, Singapore, Spain and Sweden are participating in this exercise.

Good news for Amarnath pilgrims

50% discount on hotel and taxi

New Delhi: There is good news for the devotees of Lord Shiva who are coming to participate in the Amarnath Yatra this time. In fact, to make the pilgrimage of Baba Barfani starting from July 3 easy and successful, Jammu Kashmir Hotel and Restaurant Association and tour operators have announced 50 percent discount. This relaxation will be applicable during the entire pilgrimage. Along with huge discounts, there is also a special news for the travelers that this year also Baba Barfani is seen in his full size along with Mother Parvati and son Ganesh. In such a situation, Baba Barfani, along with giving darshan to his devotees in full form, is also taking special care of their pockets. It is true that after the terrorist attack in Pahalgam, tourism in Jammu and Kashmir is slowly coming back on track. Meanwhile, to win back the trust of the people and make the journey of pilgrims safe and easy, people associated with the tourism sector have taken special initiatives. In fact, all the hotel owners and transporters of Jammu and Kashmir have announced to give 50 percent discount on accommodation, travel packages and taxi services to the tourists. Major trade organizations like Jammu Kashmir Hotel and Restaurant Association and J&K Hoteliers Club have jointly taken this important initiative. The purpose of this step is to promote tourism again. Officials expect a huge increase in registrations and an increase in the number of pilgrims.

India-Sri Lanka defense cooperation strengthened

Handed over military aid worth 5.5 million dollars

New Delhi: India's High Commissioner to Sri Lanka handed over military equipment to the Sri Lankan Army for deployment in the United Nations (UN) Mission. These equipment have been given under the assistance amount of US$ 55 lakh. India's High Commissioner Santosh Jha wrote on social media platform "India immediately arranged for these equipment upon Sri Lanka's request. This reflects the trust and confidence in the defense ties between the two countries," he said. Earlier in April, India had given two personal watercraft (PWC) and safety equipment to the Sri Lanka Coast Guard. Indian High Commission in Colombo told on 'X' that India is helping Sri Lanka Coast Guard to enhance its offshore search and rescue capability. The items were handed over by the Defense Advisor of the Indian High Commission to the Director of Operations during a program organized at the Sri Lanka Coast Guard Headquarters in Mirissa.

Israeli Prime Minister Netanyahu's threat

Iran will not be allowed to possess nuclear weapons under any circumstances

whether there is a peace agreement or not

Tel Aviv: Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu said that Iran will not be allowed to possess nuclear weapons under any circumstances, whether there is a peace agreement or not. His statement has come when an agreement has been agreed between America and Iran to reduce tension in West Asia. Netanyahu said his entire political career has been focused on the goal of preventing Iran from acquiring nuclear weapons. He called it the responsibility of his entire life. He clearly said that as long as he is the Prime Minister, he will not allow Iran to acquire nuclear weapons. On the other hand, according to US officials, President Donald Trump and Vice President JD Vance have signed an agreement with Iran, in which the framework for future negotiations and cooperation has been decided. This framework holds the potential for sanctions relief and enhanced economic ties based on Iran's cooperation, especially if it adheres to nuclear conditions and regional security norms. The US says the deal could open the way for Iran to integrate into the international economic system if it follows its commitments.

What did President Trump say?

President Donald Trump has called it a 'very strong document'. He has said that its complete details will be made public soon. Vice President JD Vance also confirmed that the digital signature has already been done. He said sanctions relief would be available only if Iran reduces its enriched uranium stockpile and accepts the required verification regime (nuclear weapons testing).

Important order of Health Ministry

Now cough syrup will not be available without doctor's prescription

New Delhi: Now doctor's prescription will be mandatory to buy various medicinal syrups including cough syrup across the country. The Central Government has decided to ban over-the-counter (OTC) sale of syrup by amending the Drugs Rules, 1945. After the implementation of the new rules, it will be necessary to show a prescription issued by a registered doctor to buy syrup from the pharmacy.

What is the new rule?

The Central Government has implemented the Drugs (Fifth Amendment) Rules, 2026 through a notification issued on 9 June 2026. This amendment has been made under Section 12 and 33 of the Drugs and Cosmetics Act, 1940 and has become effective as soon as it is published in the Official Gazette.

What changes were made in the drugs rules?

The government has removed the word "Syrups" from the category of drugs listed in Schedule K of the Drugs Rules, 1945. As a result, syrups will no longer be classified as over-the-counter medicines and their sale will be subject to strict regulatory control.

Now cough syrup will not be available without prescription

Under the new rule, to buy medicinal syrups including cough syrup, consumers will have to show a prescription issued by a registered medical practitioner. This will affect the normal purchase of those syrups, which till now people used to buy directly from medical stores.

Decision taken after cases of death of children

This step of the government has come at a time when cases of death of children due to consumption of contaminated cough syrup in Madhya Pradesh and Rajasthan had raised serious questions about the quality and monitoring of medicines. After these incidents, the demand for strict control on the manufacture and sale of syrup intensified.

Amendment implemented after taking suggestions from public

The draft of this amendment was released on 30 December 2025, on which objections and suggestions were sought from the general public. The government said that the final amendment was notified after considering the suggestions received.

Whatever be your religion, you should be a good person because your deeds will be accounted for, not your religion.

PUPILS TIMES

Only he who gives up all desires and becomes free from the feeling of 'I' and 'mine' attains peace.
Geeta Sermon

Friday, 19 June to 25 June 2026

Amidst the oil-gas crisis, Modi will give a big gift on 4th July

Petrol and diesel will now be produced from this refinery of Rajasthan

New Delhi : The much-awaited Pachpadra Refinery located in Balotra district of Rajasthan is expected to start production of petrol and diesel by the end of this month. The much-awaited Pachpadra Refinery located in Balotra district of Rajasthan is expected to start production of petrol and diesel by the end of this month. According to information received from official sources, the refinery is likely to be inaugurated by Prime Minister Narendra Modi on July 4. The commissioning of the refinery has been delayed several times this year. The inauguration ceremony was initially proposed for 28 January, which was later rescheduled to 21 April. However, the program was canceled due to a major fire on April 20 following an explosion in an exchanger unit in the Crude Distillation Unit-Vacuum Distillation Unit section of the refinery. Although the official announcement is yet to be made, preparations for the grand welcome of Prime Minister Modi are in full swing.

Instructions to start production of petroleum products

Reviewing the progress of Hindustan Petroleum Corporation Limited (HPCL) Rajasthan Refinery Project, State Chief Secretary V Srinivas directed officials to expedite the remaining works and start production of petroleum products at the earliest. During the review meeting held at the Government Secretariat, Srinivas said that preparations for petrol and diesel production are in the final stages and the production is targeted to start this month. The meeting also assessed the status of infrastructure development and ongoing works being done by various departments associated with the project. Emphasizing the importance of the refinery in the industrial development of Rajasthan, the Chief Secretary directed all concerned departments to complete the pending works within the stipulated time frame and also maintain close coordination. Senior officials including Additional Chief Secretary (Water Resources) Abhay Kumar, Additional Chief Secretary (Mines and Petroleum) Aparna Arora and Special Secretary Namrata Vrishni were present in the review meeting.

CM Yogi's ultimatum to corrupt officers

Said-I will suspend 150 officers and employees in a single day

Lucknow: Chief Minister Yogi Adityanath has given a strong message to the officials regarding negligence and corruption in redressal of public complaints. In video conferencing with senior police and administration officials, Yogi reiterated the government's 'zero tolerance' policy against corruption and said that a list of corrupt officers and employees is being prepared. Senior officers at their level should ensure action against such people with immediate effect. If action is not taken at the departmental level, he himself will take strict action. Said in a warning tone that I will take major action and suspend more than 150 officers and employees in a single day. The Chief Minister clearly said that timely and quality disposal of complaints through Janata Darshan, CM Helpline and IGRS portal is the top priority of the government. Cheating will not be accepted in this. He said that in some districts, especially the situation of redressal of complaints related to revenue and police is not satisfactory.

big action will be taken

Such districts will have to immediately improve their functioning, otherwise strict action will be taken by fixing the accountability of the concerned officers. Reiterating the government's 'zero tolerance' policy against corruption, the Chief Minister has given a strict warning to the officials. Giving instructions, he said that the intention of the government is clear that no officer or employee involved in corruption will get protection at any level. He instructed the officers to work with honesty, transparency and accountability. Said that the action should be taken so harshly that fear is created among the corrupt and the people of the state maintain faith in the government and administration.

Shivraj Singh's new plan for farmers to deal with El Nino

Crop pattern will change with intercropping

New Delhi: To deal with the effects of El Nino, a district-wise contingency plan will be made across the country. The Agriculture Ministry will hold meetings every week to formulate strategies for this. Union Agriculture and Rural Development Minister Shivraj Singh Chauhan held a review meeting of Kharif crops across the country on Tuesday. In the review meeting, Shivraj Singh said that in such districts of the country where there is a possibility of less rainfall or unevenness, complete preparations should be made in advance. For this, instructions have been given to prepare crop-wise contingency plans in collaboration with the states. Union Agriculture Minister Shivraj Singh Chauhan gave clear instructions that "Special attention should be paid to water conservation, moisture management, intercropping and alternative cropping patterns in the districts across the country where El Nino can affect, where there may be less rainfall. A separate and practical strategy should be made for each at-risk district." Union Minister Shivraj Singh Chouhan said, "In the 9-10 states where the impact of El Nino can be relatively greater, coordinated meetings should be organized with the district officers of the identified districts, agriculture department, KVK and other extension mechanisms. In these meetings, the entire situation should be clarified at the district level and an awareness campaign should be conducted among the farmers, so that every farmer knows which precautions and which crop options are safer for his area." Union Minister Shivraj Singh said, "The government's

effort is to make the country self-reliant in the matter of pulses. Dependence on imports of pulses like arhar, urad, moong should be reduced and exports should increase. For this, special focus is being put on crop cycle, area expansion, better seed availability and technical guidance in collaboration with the states.

How does El Nino work?

El Nino is a seasonal or climatic phenomenon that occurs due to the warming of the Pacific Ocean. Due to its effect, the cycle of rain and wind changes around the world. Due to which heavy rains and floods occur in some areas and drought conditions arise in some places. Due to this, along with agriculture, the economy of the country is also affected. On normal days, winds near the equator blow from east to west, pushing warm water from South America toward Asia and Australia. During El Nino, these winds weaken or change their direction. Due to this, hot water starts accumulating back towards the South American coast and the temperature of the sea increases much more than normal.

Indian Army changed uniform rules

Now Bundy jacket gets approval

New Delhi: The Indian Army has made sweeping changes to its dress regulations, taking a major step towards ending the traditions left over from the colonial era. The Army has permitted the wearing of close-necked Bundy jackets on formal occasions, while pouch belts used in ceremonies have been removed from many dress codes. Apart from this, it will no longer be mandatory for the officers inspecting during the parade to wear swords. These changes have been included in the Army's new 174-page manual "Army Uniforms-2026". According to officials, such uniform rules were last issued eight years ago. In the new rules,

old words like 'Royal' associated with the colonial period have also been removed. Adjutant General of the Army Lt Gen VPS Kaushik said in the introduction that this edition is an important step towards molding the Army's dress system in line with Indian values and contemporary national thinking.

PUPILS TIMES

Core Committee

Anurag Shukla
Chief Editor

Shivprakash Pandey
Chief Publisher

Vikas Maurya
Co Publisher

Address: Shop No. 3, Khatri NX Aprt., Valivali, Badlapur (West) - 421503
Contact: 9004331751
Web: pupilstimes.com

(The editor does not necessarily agree with the news, articles, and advertisements published in this issue. Any disputes are subject to the jurisdiction of the Mumbai courts.)

Printed, Published & Owned by : **ANIL MISRA,** Printed at **SOMANI PRINTING PRESS Printing Press,** UNIT NO.04, GROUND FLOOR, N. K. INDUSTRIAL ESTATE, OFF. AAREY ROAD, GOREGAON (E) , MUMBAI, MAHARASHTRA - 400064. **Published at:** 94, 1/3 JAI JAWAN VASAHAT, SHIVSHRUSHTI ROAD, KURLA (EAST), MUMBAI - 400024 (MAHARASHTRA)
Editor - **ANIL MISRA** Mob: **92208 68564** **Email:** anilmisrapc@gmail.com **PRGI. No.: MHMUL/25/A2419**